

दिनांक 3 जुलाई, 1987

सं० प्रो० वि०/पानी/13-86/2610.7—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० दी करनाल रोपमेंट्स शूगर मिलज लि०, करनाल, के श्रमिक श्री माम चन्द तथा अन्य 17 श्रमिक (अनुबन्ध “क”), माफत डा० मुरेन्द्र कुमार वर्मा, घर्मपाला शाहग रेनवे रोड, जगाधरी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामलों में लगे श्रीयोगिता विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट कला बांछनाय समझते हैं :

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3 (44)84-अम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद के सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :-

क्या श्री माम चन्द तथा अन्य 17 श्रमिकगण (अनुबन्ध “क”) की सेवाओं का समापन/छंटनी न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

अनुबन्ध “क”

सर्वश्री—

1. माम चन्द, पुत्र श्री रहतु राम ।
2. श्रीनिवास, पुत्र श्री लछमन दास ।
3. जगमाल सिंह, पुत्र श्री धन सिंह
4. हवा सिंह, पुत्र श्री रति राम ।
5. राम कुमार, पुत्र श्री मुला राम ।
6. नर सिंह, पुत्र श्री कालू राम ।
7. बलदेव, पुत्र श्री रिसाल सिंह ।
8. रायसिंह, पुत्र श्री अग्ने राम ।
9. कृष्ण लाल, पुत्र श्री लखी राम ।
10. जगबीर सिंह, पुत्र श्री ईश्वर सिंह ।
11. राम कुमार, पुत्र श्री दल सिंह ।
12. मोहिन्द्र पाल, पुत्र श्री कन्हैया लाल ।
13. हवा सिंह, पुत्र श्री हरफुल सिंह ।
14. जबर सिंह, पुत्र श्री रणधीर सिंह ।
15. घर्मपाल, पुत्र श्री ज्योति राम ।
16. जय भगवान, पुत्र श्री हरदेवा ।
17. महाबीर, पुत्र श्री चरंजी लाल ।
18. ब्रजमोहन, पुत्र श्री मदन लाल ।

प्रार० एस० अग्रवाल,

उप-सचिव, हरियाणा सरकार,  
श्रम विभाग ।